1

515

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–18)

निर्धारित समय: तीन घंटे Time allowed: Three Hours	GSM (M-I)-2418	अधिकतम अंक: 250 Maximum Marks: 250

Name: Siddharth Kumar Meena Mobile Number: ___

Medium (English/Hindi): Hindi Reg. Number: 36002

Center & Date: M.N. UPSC Roll No. (If allotted): 3600277

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH.***

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

drishti | दृष्टि The Vision

1. संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

The role of opposition parties is critical in determining the level of parliamentary accountability. Discuss.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसदीय उत्तरदायित्व कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। जो भारतीय संसदीय व्यवस्था का आधार है। (Art. 75)

संसदीय उत्तरदायित्व निर्धारण में विधायिका, समितियों, मीडिया, सिविल सोसाइटी सहित विपक्ष का महत्व निर्णायक है।

संसदीय उत्तरदायित्व का स्तर निर्धारण में विपक्ष की भूमिका :→

① प्रश्न पूछना :— प्रश्नकाल, शून्यकाल, लोक महत्व के चर्चा।

② बिलों का विरोध कर — सरकार द्वारा लाये जाने बिलों की कमियाँ दिखाना।
उदा० — 3 कृषि बिल पर

③ सत्ता पक्ष की रचनात्मक आलोचना

(4) सीमित तंत्र से गहन जाँच व इनपुट प्रदान करें।

(5) अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बजट पर मतदान को कमजोर दिखाकर या धन्यवाद प्रस्ताव में परिवर्तन लाकर।

(6) रचनात्मकता का स्तर बढ़ाकर (छाया कैबिनेट की तरह)

हालाँकि भारत में यह भूमिका कमजोर हो रही है

- विपक्ष का संवेदनता पक्ष से द्वंद्व
- विपक्ष सदस्य संख्या कम
- क्षमता व कौशल अभाव
- पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपात

अतः पीठासीन अधिकारी को निष्पक्ष बनाते हुए ब्रिटिश मॉडल की तरह भारतीय विपक्ष को सशक्त बनाकर जवाबदेहिता का स्तर बढ़ाया जा सकता है।

drishti | दृष्टि The Vision

2. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Discuss the role of Self-Help Groups in widening women's labour force participation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

PLFS के अनुसार महिला-श्रमबल भागीदारी दर 27% के स्तर पर है जो चिंता का विषय है।

स्वयं सहायता समूह समान विचारधारा व समान हितों से जुड़े 15-20 लोगों का समूह है।

SHG कार्यकरण
- बचत को बढ़ावा
- क्षमता निर्माण क्षमता वर्धन
- नवाचार लाना
- आपातकालीन ऋण उपलब्धता
- नेतृत्व कौशल निर्माण

उदा० - केरल का कुडुम्बश्री मॉडल व SEWA स्वयं सहायता समूह की महिला भागीदारी बढ़ाने में अहम रोल रहा है।

W-LFPR बढ़ाने में SHG : →

1. महिलाओं को एकत्रित व सशक्त बनाना → सामूहिक मांग क्षमता
2. महिला कौशल विकास द्वारा क्षमता।
3. महिला द्वारा बनाये उत्पादों को बाजार प्रदान करना।
   उदा० - सखी पोर्टल, उद्यम सखी योजना
4. महिला रोजगार परकता बढ़ाना
5. परिवार के सदस्यों की मनोवृत्ति बदलाव पर कार्य करना।

चुनौतियाँ
- वित्त कमी
- पिछड़े राज्य केंद्रित
- हार्ड
- कुछ केवल कौशल केंद्रित [illegible]
- संगठों सहायक

सुझाव
- SHG बैंक लिंकेज को सशक्त
- औपचारिकता
- बाजार विकास
- कौशल विकास

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने से समाज के कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बल मिला है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The approach to welfare is wholesome and whole-of-society, with increasing private sector participation through Corporate Social Responsibility(CSR). Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी एक्ट 2013 के तहत संविधान की अनुच्छेद 38, 39 की भावना अनुरूप निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर अपनी 3 वर्षों की वार्षिक आय के 2% को खर्च करने की प्रतिबद्धता है।

समाज कल्याण सरकार अकेले के लिए असंभावहार्य है। (जिसके निजी) क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्य है।

CSR के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी से समाज कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण: →

(i) धन का पुनः वितरण होना।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② सरकार के कल्याण कार्यक्रमों को सहायता मिलना।
उदा० - अजीम प्रेमजी द्वारा शिक्षा में

③ निजी कंपनियों द्वारा सामाजिक दायित्व

④ कंपनी को भी छवि सुधार द्वारा दीर्घकालिक लाभ → कंपनी को भी फायदा

⑤ स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कौशल विकास में सुधार
Ex - बिल एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा

⑥ पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान बढ़ाना व पर्यावरण मित्रता लाना।

अतः CSR द्वारा सभी का समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है।

समग्र स्वीकृत व विशिष्ट नीति

लक्षित क्षेत्र

सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा किसी द्वारा वितरित

और अधिक समग्र के लिए राह

प्रशासनिक खर्च मात्र 10% हो

NE भारत व सीमांत, जनजातीय क्षेत्रों में वितरण

CSR खर्च में पारदर्शिता

CSR वित्तीय रिपोर्टिंग (कोटक पैनल)

CSR के काले धन के प्रवाह पर रोक

4. व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य, कम ध्यान दिये जाने वाला लेकिन प्रभावशाली चालक है। चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार की सकारात्मक नीति क्या है? (150 शब्द) 10

Mental health is a less seen yet principally impactful driver of individual and national development. Discuss. What is the Government's positive policy momentum in this regard? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मानसिक भारत मे प्राय: व्यक्तिगत का विषय माने जाने के कारण उपेक्षित रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्तिगत व राष्ट्रीय विकास! →

मानसिक स्वास्थ्य होना

- बेहतर निर्णय क्षमता
- Drugs से बचना
- कार्यस्थल 100% दक्षता से
- आत्महत्या दर कम होना
- अपराधी बनने से बचाना
- स्वास्थ्य व्यय कम होना
- अन्य रोगों विकारों से मुक्ति मिलना
- परिवार विघटन

मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत: देश के स्वास्थ्य विकास का आधार बन जाता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अनध्यान दिये जाने के कारण

- वोट का मुद्दा नहीं
- सामाजिक कलंक
- डेटा अभाव
- प्रशिक्षित मानव बल अभाव
- पहचान का संकट
- खुलापन होना।
- नीति नहीं होना

सरकार की नीति :—

1. रिहैब की नीति → जो लोग पीड़ित है उनकी पहचान कर रिहैब।
2. प्रारंभिक स्तर पर पहचान के लिए कार्य
3. मानसिक स्वास्थ्य नीति 2017
4. डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2022 से जोड़ना
5. डेटा व संसाधन विकास
6. माता-पिता व परिवार में जागरूकता

सुझाव

- एकीकृत नीति
- लोगों की चर्चा का विषय बने
- शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़ना।
- कौशल विकास
- डेटा सुधार

drishti | दृष्टि The Vision

5. ग्रामीण भारत के शासन में सुधार हेतु शुरू की गई विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों पर चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

Discuss the multiple digitization initiatives that have been unfolding in rural India to improve governance.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

शासन का डिजिटलीकरण उसे स्मार्टशासन बना देता है, ग्रामीण भारत भी इससे अछूता नहीं है।

ग्रामीण भारत के शासन सुधार हेतु डिजिटलीकरण पहलें हैं →

① प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना द्वारा लगभग 334 योजनाओं को लाभ।
Ex - पहल योजना
- मनरेगा का पैसा सीधा अकाउंट में

② स्वयं पोर्टल द्वारा, MOOC माध्यम से शिक्षा व्यवस्था के प्रभावी निगरानी व गुणवत्ता सुधार।

③ किसान कॉल सेंटर, कृषि संबंधी

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पहलों से किसानों को तुलना व सशक्ता।

(4) e-NAM योजना द्वारा APMC को जोड़ना व किसान को मजबूत बनाना।

(5) ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ~~...~~ (7) ड्रोन टैगिंग

(6) टेलीशिक्षा टेलीमेडीशन इत्यादि।

(8) स्वामित्व योजना

फलत: प्रगति अवश्य हुई है लेकिन पर्याप्त नहीं है।

पहलों के कमियाँ →

- डिजिटल डिवाइड
- साइबर धोखाधड़ी
- बिजली संकट
- लोगों द्वारा न जुड़ना
- ईच्छा अभाव

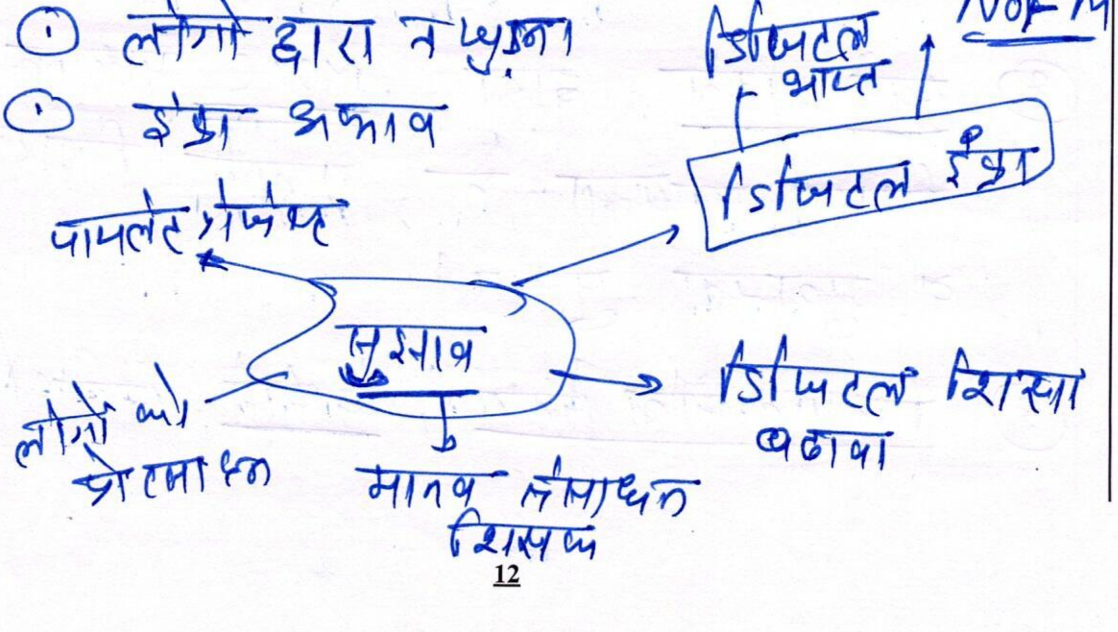

drishti | दृष्टि The Vision

6. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस लिखित संघीय संविधान को नम्यता (Flexibility) प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विस्तारपूर्वक समझाइये। (150 शब्द) 10

A distinctive feature of the Indian Constitution is that it seeks to impart flexibility to a written federal Constitution. Elaborate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संघीय लिखित संविधान की नम्यता इसे जीवंत दस्तावेज का रूप प्रदान करती है।

लिखित संघीय संविधान वस्तुतः केंद्र व राज्यों के शक्तियों के विभाजन का स्पष्टीकरण है।

मात्र लिखित होना इसे कठोर व अपरिवर्तनीय बना देता जो समय के साथ आते बहुविध बदलावों को समावेश करने से रोकता।

लिखित संविधान की नम्यता का माध्यम

(1) Art 368 द्वारा संविधान संशोधन
(2) सामान्य संविधान संशोधन
(3) साधारण व विशिष्ट संशोधन
(4) आपातकालीन प्रावधान (Art 352, 356, 360)

drishti | दृष्टि The Vision

लिखित समय संघीय संविधान का महत्व ! →

1. बदलती जरूरतों के अनुसार बदलाव
   Ex - 42 वां संविधान संशोधन द्वारा
2. मूल अधिकारों को जोड़ना, प्रस्तावना का विस्तार
3. साइबर दौर में IT Act, IT Rule लाना।
4. GST के साथ GST Council को लाना 101 वां संविधान संशोधन)
5. महिला आरक्षण विधेयक (106 वां संविधान संशोधन) को कार्यान्वित करना।
6. लद्दाख को UT बनाना

अतः यह नम्यता अवश्य विशेषता है लेकिन इसका प्रयोग संवैधानिक दायरों के अधीन ही होना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

7. न्यायिक कार्यों की पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता एक सुदृढ़ एवं प्रभावी विधिक प्रणाली की आधारशिला है, जिससे लोक विश्वास सुनिश्चित और न्यायिक सिद्धांत का कार्यान्वयन संपुष्ट होता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The transparency and accountability of judicial function form the cornerstone of a robust and effective legal system, ensuring public trust and upholding the principles of justice. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायिक कार्य वस्तुत: किसी देश की वास्तविकता, न्यायप्रियता व लोकतंत्र का आधार स्तंभ है

न्यायिक कार्य
- पारदर्शी → लोगों द्वारा जान सकना → विश्वास
- जवाबदेह → गलत के लिए रुकावट → प्रभावी

→ प्रभावी विधिक प्रणाली

भारतीय न्यायपालिका में अपारदर्शिता व गैरजवाबदेहिता :-

(1) कॉलेजियम प्रणाली की नियुक्ति अपारदर्शिता।

(2) जज द्वारा जज की नियुक्ति

(3) अंकल जज सिंड्रोम का आरोप (विधि आयोग)

(4) अवमानना पर राज्य की शक्ति से हितों का संघर्ष।

(5) संविधान की मूल संरचना व अवमानना की स्वेच्छ व्याख्याएँ। [न्यायिक सक्रियता व अतिसंयम]

↳ फलतः इससे न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता व न्यायप्रियता पर प्रश्न पैदा होता है

आगे की राह

- कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता
  - ↳ सरकार द्वारा M.O.P में सम्मिलित को महत्व
- अवमानना के मामलों के लिए पृथक आयोग स्थापना
- न्यायिक जवाबदेहिता के लिए 2010 का पालन
- न्यायिक संयमन को अपनाना
- कोर्ट की लाइव कार्यप्रणाली
- सुप्रीम कोर्ट सहित कोर्टों में निकाय विविधीकरण

8. राज्यों की राजनीतिक कार्यप्रणाली के संबंध में राज्यपालों के गैर-पक्षपातपूर्ण बने रहने से संबंधित संवैधानिक अवधारणा गहन जाँच के दायरे में है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional conception of state governors occupying a non-partisan position with regard to the political functioning of states has come under severe strain. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

'राज्यपाल का पद केंद्र का एजेंट नहीं है, वह स्वतंत्र संवैधानिक पद है' [सुप्रीम कोर्ट]

लेकिन वर्तमान दौर में राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया जा रहा है :—

① राज्यपाल द्वारा केंद्र के विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों में अति हस्तक्षेप
उदा० – तमिलनाडु व पंजाब का आरोप

② त्रिशंकु विधानसभा व सरकार के गठन के समय राज्यपाल द्वारा संविधान की उपेक्षा
उदा० – गोवा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के आरोप

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(3) Art 200 व Art 201 द्वारा राष्ट्रपति को बिल आरक्षित करना।

(4) धन्यवाद प्रस्ताव पर टकराव

(5) राज्य विधायिका के सदस्यों का एकतरफा से पक्षपात

(6) CM के व मंत्रिमण्डल के अनुरोध व परामर्श पर भी सदन का सत्र न बुलाना।

रोग क्यों जटिल → राजनीति के व्यापक मुद्दा।

- राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र का व्यापक हस्तक्षेप
- राज्यपाल का कार्यकाल व कार्यालय दोनों व्यावहारिकत: अनिश्चित
- प्राय: सत्ता पक्ष का रिटायर्ड व्यक्ति

सुझाव

- → निष्पक्षता
- → हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति जैसी
- वेंकटचलैया: केवल संवैधानिक विवेकाधिकारों में स्वायत्त रहे
- सरकारिया आयोग सुझाव ⇓
  - → राज्य की राजनीति से न जुड़ा हो
  - → राज्य से बाहर का हो
  - → नियुक्ति में CM को महत्त्व

फलत: राज्यस्तरीय संघीय लोकतंत्र के लिए राज्यपाल की निष्पक्षता अनिवार्य है।

drishti | दृष्टि The Vision

9. "कारागार सुधार न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक विधिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी है।" इस कथन के आलोक में भारत में कारागारों की स्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Prison reform is not just a moral imperative, but a legal and social necessity." In light of this statement, critically analyze the state of prisons in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत के कारागार अपनी क्षमता से 150% अधिक पर कार्य कर रहे हैं। (NCRB data)

भारतीय कारागारों की दयनीय दशा

1. कैदी संख्या > जेल क्षमता
2. जेलों के मानव संसाधन अपर्याप्त
   उदा० - प्रति 100 कैदी UN के अनुसार 10 पुलिस हो भारत में 2 के आसपास है।
3. कारागार स्वास्थ्य व स्वच्छता की दुर्दशा
   ↳ बीमारियाँ → स्वास्थ्य व्यय बढ़ना
4. विचाराधीन कैदियों की संख्या 2/3 से भी अधिक
5. कारागार सुधार की जगह मात्र लोग भरने के माध्यम बन गये हैं।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कारागार सुधार की आवश्यकता :-

(1) नैतिक रूप से जरूरी है क्योंकि इससे कैदियों का स्वास्थ सुधार व पुनर्स्थापन हो सकेगी। → कैदी का नैतिक विघटन नहीं होगा।

(2) विधिक आवश्यकता ताकि जेलों व कानून पर दबाव कम हो। विधायी प्रक्रिया में सरलता।

(3) सामाजिक रूप से पुन: वास्तविक समायोजन तभी संभव है जब जेल में सुधार हो।

सुझाव → (1) विचाराधीन कैदियों की कुल संभावित सजा के 50%. काटने पर रिहाई हो। (विधि आयोग)

(2) राजस्थान के खुली जेल प्रणाली मॉडल अपनाना।

(3) कैदोल का न्यायपूर्ण तंत्र, जेल स्वास्थ्य क्षमता बढ़ाना

(4) वैधानिक व न्यायिक सुधार द्वारा तेजी

(5) व्यापक समाज सुधार ⇒ अपराध कम होना।

drishti | दृष्टि The Vision

10. भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Discuss the need for an All-India Judicial Service (AIJS) in India, highlighting key issues and challenges in its implementation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

Art 312 के तहत उल्लेखित IAS, IPS की तरह सेवा बनाने का प्रावधान है

AIJS की आवश्यकता : →

① न्यायपालिका मे युवा ज्ञान को प्रवेश

② न्यायिक मानव बल का विविधीकरण

③ IAS, IPS की तर्ज पर राष्ट्रीय एकीकरण व प्रतिष्ठा प्रदान कर योग्यता को बढ़ावा

④ न्यायपालिका पर दबाव कम हो [~~मुकदमे~~ लंबित]

⑤ ~~क्षेत्रीय~~ एकीकृत भारतीय न्यायिक प्रणाली के अनुरूप)

सुधीर चौधरी सहित विधि आयोग रिपोर्टों व पूर्व आयोग ने इसकी सिफारिश की गई थी।

drishti
दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कार्यान्वयन संबंधी मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ :

① भाषायी संकट – राज्यों के भाषायी विविधता व ADJS से आगे जजों के लिए वादियों की भाषा समझना जटिल

② योग्य परीक्षा व पैटर्न आयोजन पाना

③ लोगों को आकर्षित करना

④ संघीय स्तर पर प्रतिरोध संभव

⑤ केंद्र-राज्य के संघीय संबंधों को सैद्धांतिकत: कमजोर बनाने का आक्षेप

⑥ परीक्षा माध्यम

अतः चुनौतियाँ अवश्य हैं लेकिन इन बहुविध विशेषज्ञों (कानूनी, न्यायिक, सामाजिक, क्षेत्रीय) को समाहित कर परीक्षण आयोग की स्थापना की जा सकती है जो आवश्यकता की जाँच करे।

drishti | दृष्टि The Vision

11. सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत की जनजातीय जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के सफल वितरण में विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite commendable efforts, there are several obstacles that hinder the successful delivery of healthcare services to the tribal population of India. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

जनजातीय जनसंख्या (~~[illegible]~~) की स्वास्थ्य दशा संबंधित 60% लोग एनीमिया ग्रस्त, 40% लोग कुपोषण ग्रसित हैं। देश की 8.6% आबादी के लिए प्रयास हुए लेकिन उनकी सफलता अपेक्षित नहीं रही है।

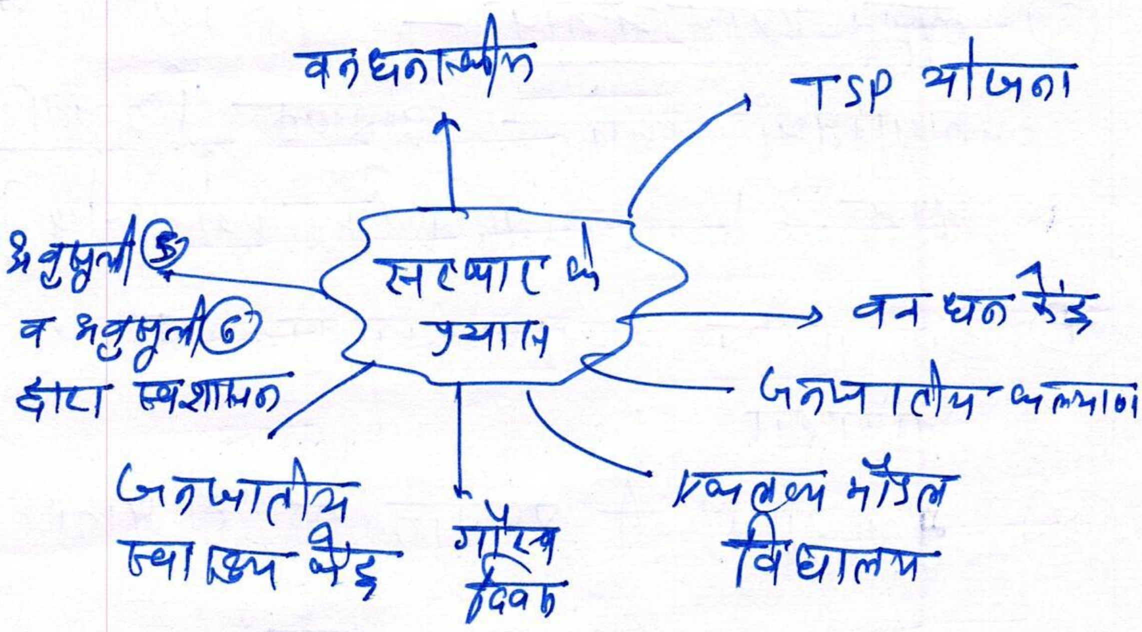

स्वास्थ्य सेवाओं के सफल वितरण में
चुनौतियाँ : →

① भौगोलिक विलगता व असंपर्क के कारण पहुँच कम होना

② स्वास्थ्य ढाँचा की दयनीय दशा
उदा० - महिलाओं द्वारा 90% गंदे कपड़े का प्रयोग (महावारी में)

③ लक्षित पोषण अभाव — 75 PVTGs व जनजातियाँ अपने विशिष्ट भिन्नताओं युक्त हैं [वन साइज फिट पोषण दोष]

④ जनजातीय अजागरूकता व अशिक्षा

⑤ मूल रोगों की पहचान न हो पाना

⑥ मदिरापान की समस्या

⑦ डिजिटल डिवाइड कारण: टेलीमेडिसिन असफल

drishti | दृष्टि The Vision

(8) मानव संसाधन क्षेत्र में कम व असंवेदनशील होना।

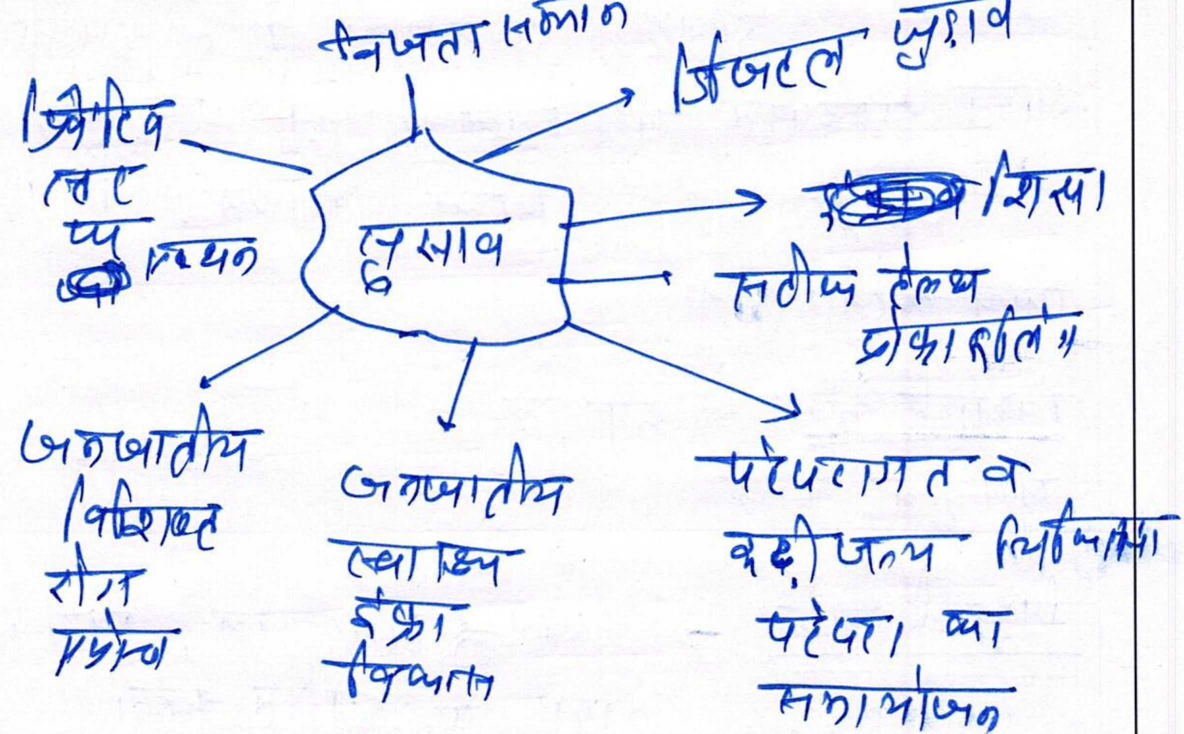

फलत: स्वस्थ जनजाति

↓

स्वस्थ प्रदेश

↓

स्वस्थ देश

⇓

समृद्ध देश

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

12. विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्यों की गणना कीजिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय संस्था और उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुधार एवं तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है? (250 शब्द) 15

Enumerate the functions of Parliament as the legislative organ. Do you agree that reforms and urgent remedial action seem imperative for making parliamentary institutions and processes effective? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसद, राज्यसभा व लोकसभा सहित राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जो बहुक्रियात्मक भूमिका विशेषत: विधायी कार्य करती है

विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्य :-

विधायी कार्य → ~~कानून~~ संसद में, विधेयक लाना व पारित करना।

→ संविधान संशोधन कार्य

→ कार्यपालिका का उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए प्रश्नकाल, शून्यकाल, परिचर्चा

उदा० - महिला आरक्षण विधेयक (106 C.A.)

अन्य कार्य - संसद विधायन के इतर कार्यपालिका, न्यायिक, वित्तीय कार्य भी

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

उदा० - महाभियोग प्रक्रिया (अनु 63), SC जज ~~SC~~ के सदस्य को पद से हटाना, वित विधेयक व बजट पर चर्चा।

हाँ, संसदीय संस्था व उसकी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सुधार व तत्काल उपचारात्मक कार्यवाई आवश्यक है।

सुधार व उपचारात्मक कार्यवाही की जरूरत क्यों

(1) संसद मात्र पस बनाम विपक्ष का अखाड़ा
(2) संसदीय बहस गुणवता पतन
(3) समितियों व्यवस्था को बिल मात्र 23% भेजना (17 वी लोकसभा)
(4) बैठको की संख्या 52, तथा कार्यउत्पादकता मे 170% की गिरावट
(5) गिलोटिन, अध्यादेश, धन विधेयक, सें: राज्यसभा की उपेक्षा
(6) राजनीति का अपराधीकरण, दलबदलता

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सुधार व उपचार हेतु सुझाव

① संसदीय संस्था
- संसदीय विशेषाधिकार परिभाषित
- → अध्यक्ष / पीठासीन अधिकारी किसी दल का सदस्य न हो
- → बिल को साधारणत: अध्यादेश से न लायें
- → दलबदल के मामलों के लिए पृथक् संसदीय जाँच आयोग हो

② प्रक्रियागत सुधार
- → मतदान प्रयोग स्पष्ट हो
- → बहस के लिए माहौल बने
- → समितियों तंत्र को बिल अनिवार्य
- → सदस्य निलंबन की प्रक्रिया में स्पष्टता
- → विधेयक लाने के अवसर गैर-सरकारी सदस्यों को अधिक दें
- → संसदीय बैठक कम से कम 120 दिन

फलत: संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशों को अपनाया जाना चाहिए।

13. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कम विरोधाभासी होने के साथ विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये। इस दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं? (250 शब्द) 15

Alternate Dispute Resolution mechanisms are less adversarial and can provide a better substitute to the conventional methods of resolving disputes. Discuss. What are the government's efforts to bring out a transformative shift towards it? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र सामान्य कोर्ट व कोर्ट प्रक्रियागत जटिलता के बाहर विवाद का जीत-जीत के सिद्धांत पर आधारित समाधान प्रयास है।

पारंपारिक तरीकों से बेहतर विकल्प होना :-

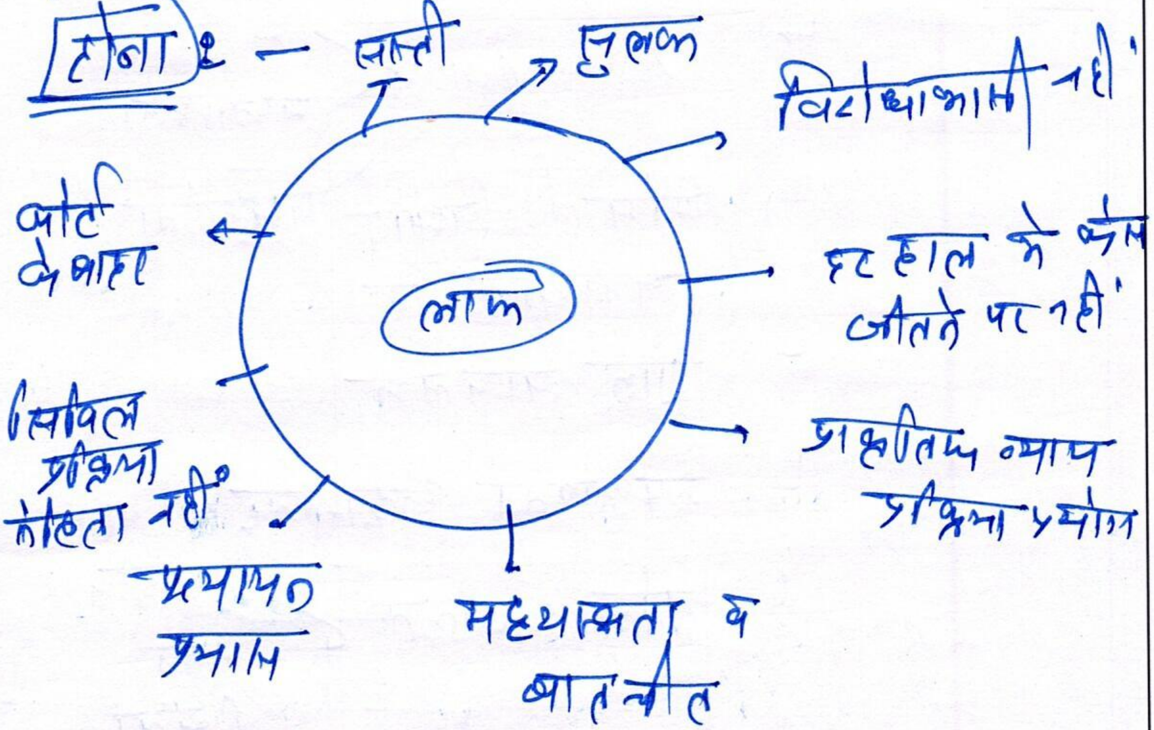

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरकार द्वारा प्रयास: →

कानूनी → NALSA का गठित करना
↳ Art 39 की भावना का कार्यान्वयन
↳ मध्यस्थता व सुलह समाधान कानून बनाना।

संस्थागत → स्पेशल कोर्ट
↳ ADR तंत्र — सुलह / मध्यस्थता / समझौता
↳ वाणिज्यिक विवाद समाधान तंत्र
↳ ग्राम न्यायालय
↳ उपभोक्ता अदालत
↳ लोक अदालत — राष्ट्रीय / राज्य / जिला
↳ न्याय आपके द्वार

योजना :- प्रो बोनो लीगल सर्विस

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रभाव : कमियाँ विद्यमान : —

- अवसंरचना का संकट
- अजागरूकता
- अपील करना
- मानव संसाधन अभाव
- जटिलता

सुझाव : —

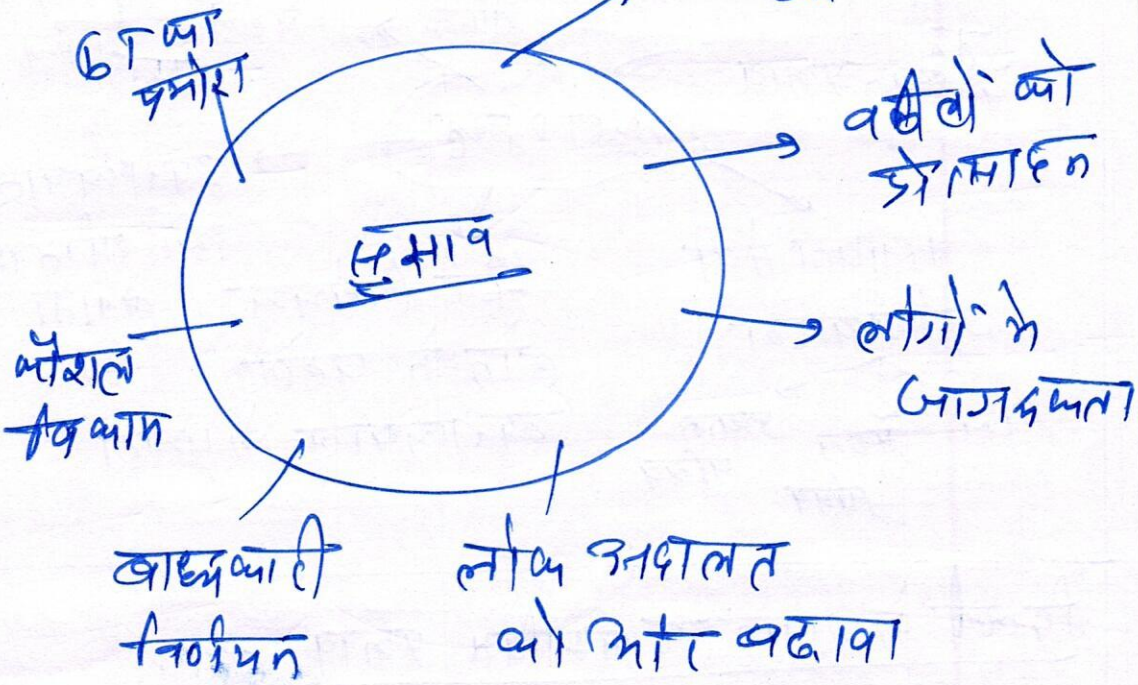

विवाद समाधान न केवल न्यायपालिका पर बोझ कम करेगा बल्कि समय व धन की बचत करते हुए कर विकास को बढ़ावा।

drishti | दृष्टि The Vision

14. दिल्ली के शासन और भारत के संघीय ढाँचे पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Critically examine the provisions of the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) (Amendment) Act, 2023 considering its potential impact on the governance of Delhi and the federal structure of India.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

GNCTD एक्ट 2023 दिल्ली के शासन सहित देश की संघीय व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव रखता है।

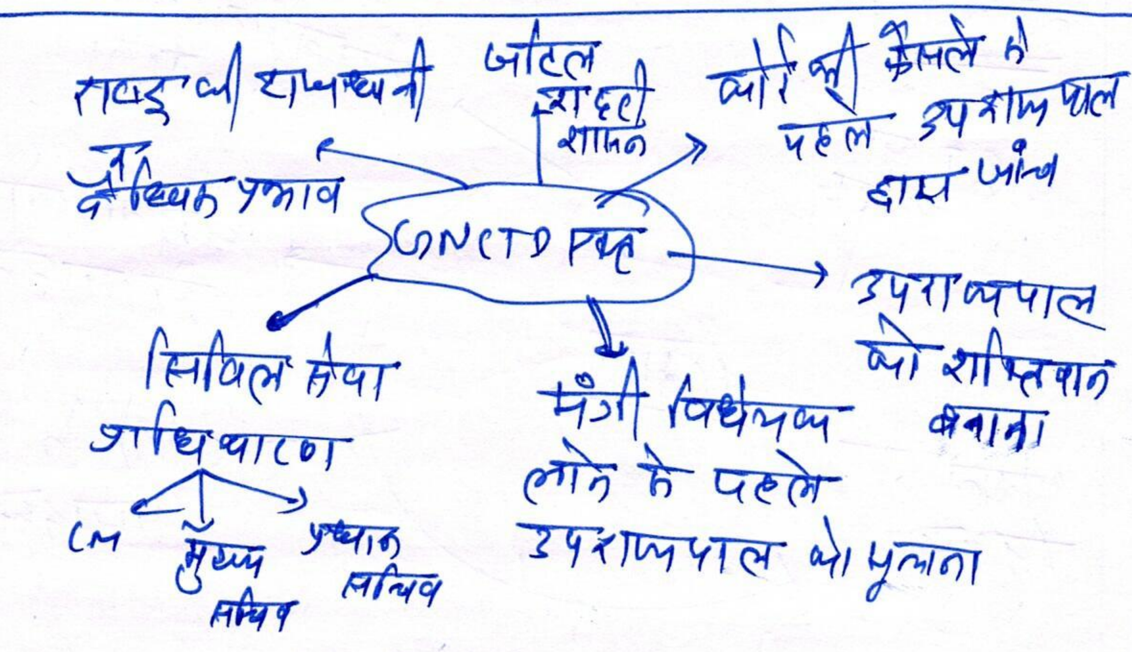

<u>दिल्ली के शासन पर संभावित प्रभाव :-</u>

① सिविल सेवकों पर मंत्री का नियंत्रण न होना जो त्रिस्तरीय नियंत्रण व्यवस्था के विपरीत।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(2) प्रावधान के बहुमत द्वारा फैसले करना: निर्वाचित CM को दरकिनार करना आसान।

(3) सरकार पर बिना शक्ति के जनता की जवाबदेहिता

(4) उपराज्यपाल का अति नियंत्रण प्रशासन में

भारत के संघीय ढाँचे पर प्रभाव :-

(1) केंद्र-राज्य संबंधों में दिल्ली को कमजोर करना

(2) जनता की आवाज को शक्तिवान प्रतिनिधित्व न मिल पाना

(3) Art 239A की भावना का उल्लंघन

(4) दिल्ली की प्रांतीय सरकार पर उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र का हस्तक्षेप

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

UNCTD क्षेत्र क्यों जरूरी :-

① दिल्ली में देश-विदेश के संस्थान व एजेंसी।

② राष्ट्रीय राजधानी व वैश्विक पहचान

③ SC, HC, NGT, संसद सहित महत्वपूर्ण कार्यालय

④ जटिल शासन तंत्र

फलतः पूर्ण स्वायत्त जैसा राज्य बनाना जटिल है क्योंकि यह विभ्रमण देश की छवि को बेहतर बनाता है।

यद्यपि संघवाद की मूल भावना का सम्मान रखते हुए न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर जैसे शहरों के शासन के अध्ययन द्वारा अनुकूलतम उपाय किये जाये।

15. भारतीय लोकसभा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष की भूमिका की तुलना कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये भूमिकाएँ अपने-अपने विधायी निकायों की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। (250 शब्द) 15

Compare and contrast the role of speaker in the Indian Lok Sabha and British House of Commons . Discuss how these roles impact the functioning of their respective legislative bodies. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के संचालन व प्रभाविता के लिए निर्णायक संवैधानिक पद है (Art 88)
ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स के यह पद प्रेरित है

भारतीय लोकसभा अध्यक्ष	ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स
① सदस्यों द्वारा निर्वाचन	① सदस्यों द्वारा
② 5 साल तक पद	② आजीवन पद
③ प्रभावी बहुमत द्वारा पद से हटाना संभव	③ हटाने का ढंग नहीं
④ राजनीतिक दलों से पूर्ण तटस्थता जरूरी नहीं	④ किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(5) सदन के सदस्य फैसला अंतिम लेकिन मूल भावना के आधार पर न्यायिक जाँच संभव	(5) अंतिम फैसला कोई जाँच नहीं
(6) लोकप्रिय विशेषाधिकार अलिखित व संहिताबद्ध ~~व अपरिभाषित~~ विशेषाधिकार	(6) विशेषाधिकार संविधान परिभाषित ~~किए~~ व समाप्त

भूमिकाओं का प्रभाव

भारत	ब्रिटेन
(1) विधायन ~~में~~ सदन का संचालन	(1) सदन संचालन
(2) कार्य प्रक्रिया नियम बनाना	(2) कानून प्रक्रिया व स्पष्टीकरण
(3) सदस्यों पर कार्यवाही	

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) अनुचित आचरण पर सदस्यों का निलंबन	(4) जाँच समिति द्वारा आचरणों की जाँच करना
(5) विपक्ष की माँगों को महत्व	
(6) दलबदल संबंधी शक्ति	(6) ऐसी कोई शक्ति नहीं

यद्यपि ब्रिटेन के अध्यक्ष की पूर्ण राजनीतिक तटस्थता उसे अधिक व्यापक व स्वतंत्र बनाती है।

भारत के अध्यक्ष पद को राजनीति से पूर्ण तटस्थ व स्थायी बनाया जाना चाहिए व आजीवन पेंशन की व्यवस्था कर विपक्ष को बढ़ावा दे।

इस संदर्भ में दलबदल संबंधी शक्ति का समयबद्ध व (राष्ट्रपति - निर्वाचन आयोग) द्वारा प्रयोग हो व संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करना चाहिए।

drishti | दृष्टि The Vision

16. राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने एवं केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में वित्त आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically evaluate Finance Commission's crucial role in ensuring fiscal federalism and maintaining a balance between the fiscal powers of the central and state governments. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राजकोषीय संघवाद केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय शक्तियों का वितरण व स्वायत्ता को संदर्भित करता है।

राजकोषीय संघवाद
- करों का वितरण (Art 267, 268,)
- करों की राशि का वितरण
- उधार लेने की शक्ति
- बजट शक्ति

वित्त आयोग (Art 280) इन दोनों के बीच वित्तीय शक्तियों के संतुलन द्वारा राजकोषीय संघवाद के महत्त्वपूर्ण है।

वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संतुलन
- केंद्र व राज्य के बीच
- राज्य व राज्य के मध्य (औचित्य)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वित आयोग की भूमिका का मूल्यांकन:

सकारात्मक:

① राज्यों को पर्याप्त वित आंवटन।
(वर्तमान के 41% कुल राजकोष)

② करों का युक्तिसंगत वितरण, संकलन व विभाजन

③ राज्यों के संसाधन बढ़ाने हेतु सुझाव

④ राज्य वित आयोग की सशक्तता के लिए सुझाव

⑤ राज्यों के मध्य वितरण के सन्तुलन फॉर्मुला का निर्माण
- जनसांख्यिकी परिवर्तन का महत्व
- आय विषमता
- वनावरण
- जनसंख्या etc.

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सीमितता : →

1. राज्यों द्वारा विशेष राज्य की सतत मांग। (आंध्रप्रदेश, बिहार)
2. दक्षिण के राज्यों के विभाजन नीति का आरोप व असंतोष
   Ex - तमिलनाडु
3. वित आयोग मात्र सलाहकारी
4. वित आयोग द्वारा राज्यों ~~के~~ ~~कि~~ वित आयोग को सशक्त न बना पाना।
5. प्रादेशिक विषमता व असंतोष
6. घाटे की अर्थव्यवस्था

फलत: वित आयोग की अधिक सशक्तता, स्वायतता व इसके फॉर्मूला मे सुधार आधारित संशोधन व नवाचार 16 वे वित आयोग के लिए जरूरी है।

17. क्या भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिये अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Has India leveraged its soft power to enhance its global stature and influence? Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सॉफ्ट पावर किसी देश की उसके व्यवहार, संस्कृति, मूल्य व लोगों से बनी शक्ति है।

भारत की सॉफ्ट पावर
- योग
- गांधीवादी विचार
- गुटनिरपेक्षता
- आयुष
- संस्कृति, मूल्य
- खान-पान
- बॉलीवुड
- प्रवासी समुदाय
- मानवीय सहायता

हाँ, भारत ने लाभ उठाया है।

वैश्विक स्थिति व प्रभाव बढ़ाने में लाभ :-

① प्रवासी समुदाय के माध्यम से संपर्क
  L आर्थिक व तकनीकी संबंध बढ़ना

② भारत की मनोरंजन उद्योग का मध्यपूर्व व SE Asia में व्यापक प्रभाव

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

③ कृषि संरता — विश्व को थामा देना

④ बुद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समग्र बहुलवाद की संस्कृति के सभी देशों के जुड़ाव।

⑤ विप्रेषण आय द्वारा आर्थिक सशक्त को पूर्व व उपायों को मजबूती

यद्यपि सॉफ्ट पॉवर का यथोचित विकास व लाभ नहीं उठाया गया है।

सुझाव

① प्रवासियों से संपर्क व उनके कल्याण व काम दशा सुधार के लिए योजना व नौतिक सहयोग।

drishti | दृष्टि The Vision

② भारत के सॉफ्ट पॉवर के महत्त्व को वैश्विक मंचों पर दिखाना।
Ex - SCO (शंघाई सहयोग) के पंचशील

③ भारत के पड़ोसी देश विशेषतः चीन पर बढ़त बनाने को
Ex, मंदारिन की तुलना में हिंदी बन वैश्विक

④ दक्षिण-दक्षिण सहयोग द्वारा वैश्विक महत्त्व बढ़ाना।

फलतः सॉफ्ट व हार्ड दोनो शक्तियों का युक्तिसंगत समायोजन समय की मांग है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

18. अपनी स्थापना के बाद से पिछले दो दशकों से अधिक समय में, बिम्सटेक (BIMSTEC) ने अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए सामूहिक उन्नति की दृष्टि वाले समूह के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

In the past more than two decades since its establishment, BIMSTEC has come a long way in distinguishing itself as a group with a vision for collective advancement utilizing its vast potential. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

बिम्सटेक दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया देशों का व्यापारिक आर्थिक संगठन है। जिसकी क्षमता विशाल है।

भारत म्यांमार
भूटान
नेपाल
श्रीलंका

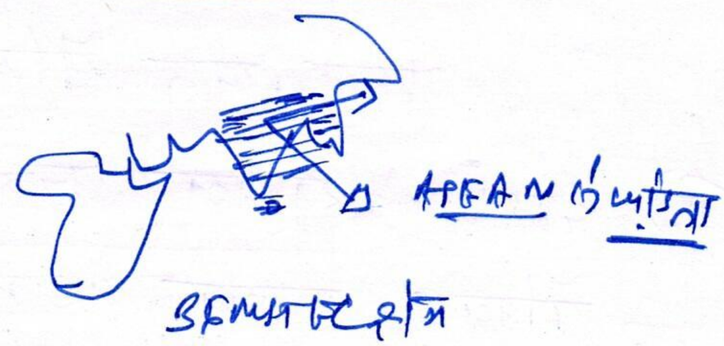

बिम्सटेक की क्षमता

- दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ना
- पाकिस्तान जैसे अवरोध रहित
- ASEAN जैसे ब्लॉक से जोड़ना
- व्यापार विस्तार

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

बिम्सटेक द्वारा अलग पहचान के रूप में प्रगति। →

① आयात बढ़ाना
② बिम्सटेक सहयोग पारिपथ
③ बिम्सटेक चार्टर का पालन
④ पंचशील की भावना
⑤ आर्थिक रूपान्तरण बढ़ना
⑥ भारत द्वारा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, म्यांमार - भारत - थाईलैण्ड सड़क निर्माण
⑦ मेकांग गंगा सहयोग को बढ़ावा
⑧ पर्यटन व लोगों का संपर्क बढ़ना
⑨ दक्षिण एशिया सैटेलाइट विकास

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

- व्यापार घाटा
- चीन का व्यापक प्रभाव
- आंतरिक संघर्ष व सीमावर्ती अस्थिरता
- प्रतिबंधों की स्थिति पर
  Ex: अभी तक FTA न होना।
- प्रतिस्पर्धी (ASEAN, सार्क से)

सुझाव:

1. पश्चिम के साथ जुड़ना
2. बढ़ती पौद्योगिकी को केंद्रीयता
3. FTA लाना
4. पारस्परिक बहुविध संपर्क
5. तकनीकी सहयोग बढ़ाना

drishti | दृष्टि The Vision

19. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते वैश्विक ऋण संकट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रमुख परिणामों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Examine the major outcomes of soaring global debt crisis in emerging and developing economies on international relations. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वैश्विक ऋण संकट किसी देश की आर्थिक दुर्दशा का संकेत है जब वह सहायता हेतु बाह्य संगठनों या देशों पर निर्भर होता है।

उदा० - पाकिस्तान, श्रीलंका, इटली, ग्रीस।

वैश्विक ऋण संकट से मुख्यतः उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्था अधिक प्रभावित है।

- अफ्रीका महाद्वीप → चीन की ऋणजाल नीति
- दक्षिण एशिया → पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल
- लैटिन अमेरिका →

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वैश्विक ग्रहण संकट (उभरती व विकासशील) का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर –

① उभरती देशों की संप्रभुता एवं समझौता

② चीन की विस्तारवाद को आधार मिलना

③ देशों के अस्थिरता व सिविल वार — पलायन → संबंध प्रभावित

④ व्यापार का कम होना

⑤ मोनोपली बढ़ने का खतरा

⑥ भौगोलिक संतुलन बिगड़ना।

उदा० – middle east के नदी के पक्ष
– एशिया के चीन के पक्ष में

⑦ वैश्विक संगठन अप्रभावी
Ex – WB, WTO

⑧ आर्थिक व्यापार संरक्षणवाद बढ़ना

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

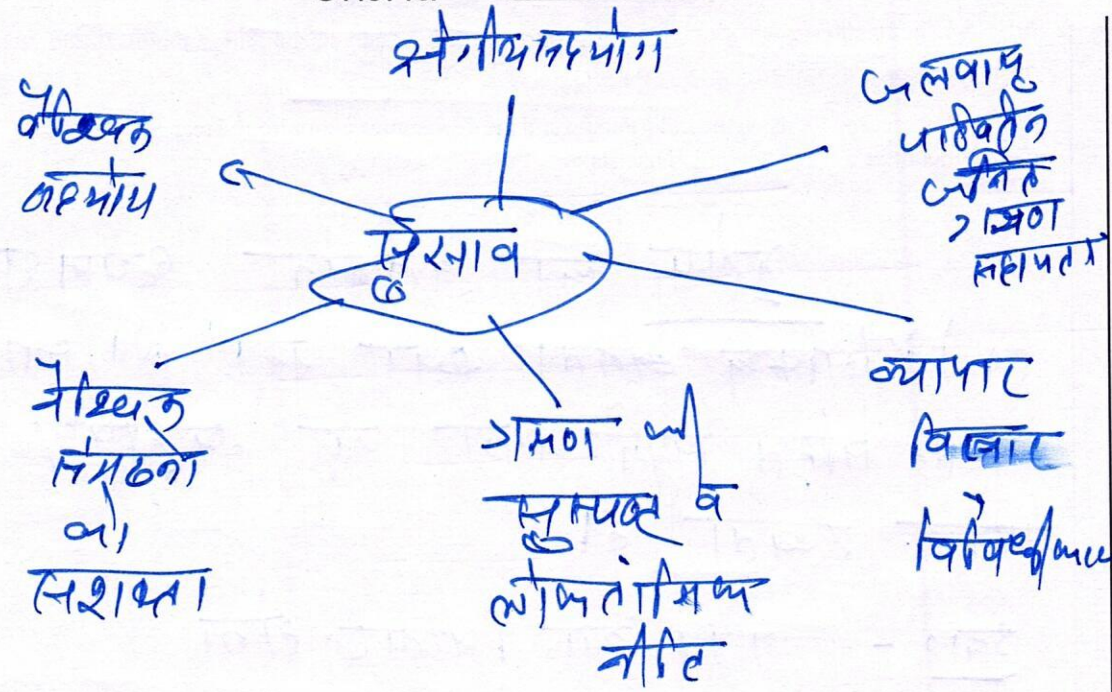

20. यूरोप का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ता ध्यान तथा भारत के साथ गहराता आर्थिक और तकनीकी सहयोग परस्पर लाभ प्रदान करता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Europe's increased focus on the Indo-Pacific and the deepening economic and technological collaboration with India offer mutual benefits. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

यूरोप का वर्तमान ध्यान क्षेत्र इण्डो-पैसिफिक बनता जा रहा है। जो भारत सहित संपूर्ण क्षेत्र पर अद्वितीय प्रभाव रखता है

उदा० - TPP का निर्माण होना

- AUKUS की स्थापना

भारत के साथ बढ़ता आर्थिक व तकनीकी सहयोग :- →

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

① भारत व EU व भारत व यूके के आर्थिक व्यापार व FTA के लिए ~~[illegible]~~ बातचीत उल्लेखनीय है।

② फ्रांस के साथ रक्षा ~~[illegible]~~ व तकनीकी सहयोग → (राफेल विमान)

③ तकनीकी सहयोग परिषद का विकास

④ EU के साथ व्यापार 100 b $ होना।

यूरोप का हिंद प्रशांत पर ध्यान व भारत से आ० -तकनीकी सहयोग से परस्पर लाभ ! —

① भारत को :-

(i) चीन को प्रतिसंतुलन करने (रणनीतिक)

(ii) ब्लॉग को नेट सुरक्षा प्रदाता बनाना

(iii) यूरोप के साथ व्यापार व वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ना

(iv) खुला, लोकतांत्रिक नेविगेशन युक्त इण्डो-पैसिफिक। (v) GTGR संतुलन

(vi) नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकी

यूरोप को लाभ :

(i) आर्थिक-व्यापार का विविधीकरण

(ii) भारत के रूप में बड़ा बाजार

(iii) चीन की मोनोपोली पर नियंत्रण

(iv) SC Mng में प्रभुत्व जमाना

(v) भारत चीन को संतुलित करने में सफल

फलतः भारत को तकनीकी व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए लेकिन इसके पॉलिसी मामलों में सतर्क भरे कदम उठाने चाहिए।

drishti | दृष्टि The Vision

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

drishti | दृष्टि The Vision

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

AUKU

75